

# शीतकालीन सत्र के पांचवें दिन भी विपक्ष का हंगामा, दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित

भाजपा सरकार में हरियाणा में कानून व्यवस्था का हुआ बंटोधार: भूपेंद्र सिंह हुड्डा

हरियाणा, 29 नवम्बर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्ता में आई है तब से राज्य की कानून व्यवस्था का बंटोधार हो गया है। हुड्डा ने कहा कि आज प्रदेश में कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता है जबकि प्रत्येक सरकार की पहली जिम्मेदारी अपनी नागरिकों को सुरक्षा देना होती है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने सोनीपत में पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में रोज 3-4 हत्याएं, 4-5 बलात्कार और दर्जनों चोरी, लूट, डकैती की वारदात होती हैं तथा



अपराध व नशे में हरियाणा ने बड़े-बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। हुड्डा कई सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करने सोनीपत पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा की नई सरकार की विफलताएं भी शुरूआत में ही उजागर हो गई हैं तथा नई सरकार भी भाजपा की पिछली सरकारों की तरह किसानों को ना खाद दे पाई और ना ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)।

नई दिल्ली, 29 नवम्बर। संसद के शीतकालीन सत्र में आज भी गतिरोध जारी रहा। दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामा के वजह से आज की कार्यवाही को स्थगित करनी पड़ी। इसका मतलब साफ है कि शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह में संसद के दोनों सदनों में कामकाज नहीं हो सका। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 25 नवंबर को हुई थी और विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण पहले सप्ताह में कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हो पाया। अब सोमवार 2 दिसंबर 2024 को सुबह 11 बजे से दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होगी। लोकसभा की सदस्यता की शपथ



लेने के एक दिन बाद शुक्रवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा सदन पहुंची और विपक्षी सदस्यों के साथ एकजुटता दिखाते हुए उनके साथ प्रदर्शन में शामिल हुईं। विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की बैठक शुक्रवार को एक बार के स्थगन के बाद पुनः शुरू होने के करीब 10 मिनट के अंदर दोपहर बारह बजकर 10 मिनट पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गयी। सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया, कांग्रेस और सपा के सदस्य आसन के समीप आकर नारेबाजी

करने लगे। कांग्रेस सदस्य अदाणी समूह से जुड़े मामले को उठा रहे थे, वहीं सपा सांसद संभल हिंसा का मुद्दा उठाते देखे गए। हंगामे के बीच ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कुछ पूरक प्रश्नों के उत्तर भी दिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम

बिरला ने सदन में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच शुक्रवार को कहा कि देश की जनता सांसदों एवं संसद के बारे में चिंतित है तथा वह चाहती है कि सदन की कार्यवाही चले। उन्होंने यह टिप्पणी प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों से सदन की बैठक

चलाने देने की अपील करते हुए की। बिरला ने इस दौरान नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों से कहा, देश की जनता चाहती है कि सदन चले। कई माननीय विद्वानों ने लिखा है कि संसद चलनी चाहिए, चर्चा-संवाद होना चाहिए। सहमति और असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत है। उनका कहना था, मैं आग्रह करता हूँ कि जनता की भावनाओं और उनकी आशाओं एवं आकांक्षाओं के अनुसार, आप सदन चलाने में सहयोग करें। आज स्वास्थ्य एवं महिलाओं पर प्रश्नकाल में चर्चा हो रही है। प्रश्नकाल आपका समय है। अदाणी समूह के

खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों और दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति सहित विभिन्न मुद्दों पर तत्काल चर्चा कराए जाने की मांग खारिज होने के बाद शुक्रवार को विपक्ष ने राज्यसभा में हंगामा किया, जिसके कारण उच्च सदन की कार्यवाही आरंभ होने के कुछ ही देर बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के भीम सिंह और जनता दल (यूनियटेड) के संजय झा को जन्मदिन की बधाई दी गई। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए।

## मांगों को लेकर संविदा कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल डिस्कॉम से मिला

वाराणसी। संविदा मजदूर संगठन के बैनरतले शुक्रवार को संविदा कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्वांचल डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक शम्भू कुमार से मिला। इस दौरान सौंपे गए पत्र में निजीकरण सहित कई समस्याओं के निराकरण की मांग की गयी। साथ ही बताया है मांगों पर ध्यान न देने की स्थिति में 3 दिसंबर को उग्र आंदोलन किया जायेगा। कर्मचारियों का कहना है कि पूर्वांचल विद्युत निगम वाराणसी एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम आगरा के बिनिवेश और निजी कर्मचारियों के साथ संयुक्त उद्यम बनाए जाने के परिणामस्वरूप निगमों में कार्यरत संविदा कर्मियों की रोजी पर



उत्पन्न खतरे को देखते हुए विद्युत संविदा मजदूर संगठन उग्र द्वारा संयुक्त उद्यम बनाए जाने की कार्रवाई को रोकने की जरूरत है। संगठन के पूर्वांचल अध्यक्ष इंद्रेश कुमार राय ने बताया कि संगठन द्वारा संविदा में कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम 22000 एवं लाइसेंस और कम्प्यूटर आपरेटर को 25000 वेतन दिए जाने और सेवा अवधि की उम्र 58 वर्ष किए

जाने सहित सात लम्बित मांगों का जल्द निपटारा किए जाने की मांग की गई है। कर्मचारियों का कहना है कि हम लोगों को विभाग द्वारा कोई सुविधा नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथियों का काम करते समय निधन हो जाता है। इसके अलावा मनमाने तरीके से कर्मचारियों का तबादला कर दिया जा रहा है। शासन द्वारा नियम का पालन नहीं किया जा रहा है और विद्युत मजदूर से मनमाने तरीके से काम लिया जा रहा है। संविदा कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है लेकिन उनके सुविधाओं का ध्यान नहीं दिया जा रहा और बिना कारण कुछ कर्मचारियों को निकालकर नये लोगों की भर्ती कर लिया जा रहा है।

## सीडब्ल्यूसी की बैठक में बोले खड़गे, हालिया विधानसभा चुनावों में धक्का लगा है, हमें कठोर निर्णय लेने होंगे

नई दिल्ली, 29 नवम्बर। कांग्रेस कार्य समिति की शुक्रवार को बैठक हुई जिसमें महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में पार्टी के हालिया चुनाव प्रदर्शन पर चर्चा की गई। आगामी दिल्ली चुनाव और संसद सत्र के लिए रणनीतियां भी एजेंडे में थीं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्व प्रमुख राहुल गांधी, एआईसीसी महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा, केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश शामिल थे। सीडब्ल्यूसी ने विभिन्न चुनाव परिणामों का विश्लेषण किया। पार्टी के गठबंधन को झारखंड में जीत तो मिली, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा में



उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सीडब्ल्यूसी की यह बैठक संभावित गठबंधनों सहित दिल्ली और बिहार में आगामी चुनावों की तैयारी पर भी फोकस थी। बैठक में खड़गे ने कहा कि हमें तुरंत चुनावी नतीजों से सबक लेते हुए संगठन के स्तर पर अपनी सभी

कमजोरियों और खामियों को दुरुस्त करने की जरूरत है, ये नतीजे हमारे लिए संदेश हैं। उन्होंने कहा कि आपसी एकता की कमी और एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हमें काफी नुकसान पहुंचाती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरी

है कि हम सख्ती से अनुशासन का पालन करें और एकजुट रहें।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हम पुराने ढर्रे पर चलते हुए हर समय सफलता नहीं पा सकते, हमें समय से निर्णय लेने होंगे और जवाबदेही तय करनी होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ईवीएम ने चुनावी प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया है, महाराष्ट्र के परिणाम ऐसे हैं कि कोई भी अंकगणित इसे उचित ठहराने में असमर्थ है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हालिया विधानसभा चुनावों में हमें धक्का लगा है, इसीलिए हमें कठोर निर्णय लेने होंगे।

## अनियंत्रित गाड़ी तालाब में पलटने से चार की मौत, तीन घायल

अरवल। बिहार में अरवल जिले के कलेर प्रखंड में कामता गांव से बारातियों को लेकर पटना जा रही एक गाड़ी के बृहस्पतिवार को अनियंत्रित होकर एक तालाब में पलटने से वाहन सवार चार लोगों की मौत हो गई जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। थाना प्रभारी मोहम्मद अली साबरी ने बताया कि प्रसादी इंग्लिश मुहल्ला के पास एक वाहन तालाब में पलट गया जिससे एक ही परिवार के तीन सदस्यों सहित चार लोगों की मौत हो गई एवं तीन अन्य व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से शवों को तालाब से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। इस हादसे में जख्मी तीन अन्य घायलों का प्रारंभिक उपचार सदर अस्पताल किया गया है।

## केंद्र सरकार से नहीं संभल रही दिल्ली की कानून व्यवस्था: अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली, 29 नवम्बर। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ कड़ी आलोचना की और उस पर दिल्ली को 'गैंगस्टर्स' द्वारा शासन करने की अनुमति देने का आरोप लगाया। दिल्ली विधानसभा में आप विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में, दिल्ली की कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है, खासकर 2019 के बाद से जब अमित शाह गृह मंत्री बने। वह दिल्ली को संभाल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हत्या की घटनाएं अक्सर हो रही हैं।

फिल्मों में देखा वो आज दिल्ली में हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में अपहरण रहे हैं। महिलाओं का अपहरण, बलात्कार और हत्या कर दी जाती है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कहर बरपाया है। लॉरेंस बिश्नोई खुद साबरमती जेल में बंद हैं जो बीजेपी शासित राज्य गुजरात में स्थित है। उन्होंने सवाल किया कि वहां की जेल से वह दिल्ली में रंगदारी का रैकेट कैसे चला रहा है?

इससे पहले दिल्ली विधानसभा के पांच साल के कार्यकाल के अंतिम सत्र के पहले दिन शुक्रवार को बस मार्शलों को हटाने के मुद्दे पर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए।

## संभल केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, निचली अदालत न ले कोई एक्शन, लिफाफे में सीलबंद रखा जाए सर्वे रिपोर्ट

नई दिल्ली, 29 नवम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया कि जब तक संभल मस्जिद की शाही इंदगाह कमेटी हाईकोर्ट नहीं जाती, तब तक मामले को आगे न बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अपने समक्ष लंबित रखा और मामले को 6 जनवरी, 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई के लिए पोस्ट किया। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संभल में शांति और सद्भाव कायम रखा जाए, रउ ने एक आदेश पारित कर मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने और ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि कमिश्नर को



अपनी रिपोर्ट सीलबंद कवर में दायित्व करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वह मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहा है। रउ ने उनसे (मस्जिद समिति से) आदेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती देने के लिए कहा है और इसे दायर किया गया है और इसे 3 कार्य दिवसों में HC के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर सीमित रोक है। इससे

पहले संभल सांसद जिया उर रहमान बर्क ने कहा कि समाजवादी

पार्टी मांग कर रही है कि जांच समिति में सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज को शामिल किया जाए। सपा नेता ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर जो मामला जिला अदालत में है, उसे रोका जाए और मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जाए। पूजा स्थल अधिनियम का सही उपयोग होना चाहिए। अब अजमेर दरगाह को लेकर भी याचिका दायर की गई है।

ये सब कब रहेगा?...कुछ चुनिंदा लोगों को माहौल बिगाड़ने का मौका क्यों दिया जा रहा है? आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चन्द्रशेखर आजाद ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के गलत कामों को रोकने का काम किया है। इस बार भी हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट जो अत्याचार हो रहा है उसे रोकने में मदद करेगा। इसको लेकर संसद में

एक संशोधन बिल आना चाहिए, 1991 के (पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम) के संबंध में एक संशोधन बिल आना चाहिए एवं पिछले बिल की कमियों को दूर किया जाये। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना चाहिए। मुझे लगता है कि पूजा स्थल अधिनियम की अपनी पवित्रता है और अयोध्या फैसले और सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ रास्ते तय किए हैं।

**“स्वच्छ जल से ही स्वस्थ जीवन”**  
सस्ते एवं उचित दर पर, आपकी सेवा में समर्पित, एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें

**पुर्णिमा सर्विसेस**

COMPLETE SOLUTIONS OF WATER TREATMENT  
ALL TYPES WATER PURIFIER SERVICE

Email - purnima.services@gmail.com  
8655185584

Shop No. 7, Gr. Floor, Prema Tower, Diva - Shil Road, Diva (E) - 400612

**THE DOCTORS COACHING**  
Your Gateway to Success in NEET & Foundation Exams!  
Powered by- Modern Kids Education Pvt. Ltd. (Since 1999)

**NEET (UG) & FOUNDATION**  
Physics Chemistry Biology

9th, 10th, 11th & 12th  
Smart Classes Fully Air-Conditioned Classes

The Doctors Coaching  
Your Gateway to success in  
**NEET**  
a foundation exams!

**ADMISSION OPEN NOW!**

www.thedoctorcoaching.com | edu@thedoctorcoaching.com  
+91-7080403322, +91-8400043322  
Near LHPs, Friends Colony, Sector-7, Vikas Nagar, Lucknow-226022







